दिनांक- 11.05.26 समय-07.10पीएम

आकाशवाणी, भोपाल

सांध्यकालीन समाचार

मुख्य समाचार,

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- सोमनाथ मंदिर देश के सभ्यतागत साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक।
- भोपाल में इंडो-फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव कल, जुटेंगे फ्रांस की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि, मध्यप्रदेश में निवेश पर होगा मंथन।
- देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर मध्यप्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपये का भुगतान।
- प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 57, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में विमुक्त किए 2 मादा चीते।

प्रधानमंत्री-सोमनाथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर गौरवशाली और शाश्वत है और देश के सभ्यतागत साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक है। श्री मोदी ने आज गुजरात में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि पवित्र सोमनाथ मंदिर में लहराता ध्वज भारत की आस्था की विजय का प्रतीक है और लाखों भारतीयों की सामूहिक चेतना की दिव्य घोषणा भी है।

विकसित भारत जी राम जी

केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी- गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष पहली जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की रोजगार गारंटी का अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। देशभर में नए ढांचे के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95 हजार 692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इंडो-फ्रेंच कॉन्क्लेव

भोपाल में कल इंडो-फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो-फ्रेंच चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि,

वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक, तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इको-सिस्टम से अवगत कराएगी।

रुस्तमजी पुरस्कार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित के.एफ. रुस्तमजी पुरस्कार वितरण समारोह में सहभागिता कर वर्ष 2019-20 तथा 2021-22 के अंतर्गत परम विशिष्ट, अति विशिष्ट एवं विशिष्ट श्रेणी के पुरस्कार प्रदान करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, इसलिए उनके व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं एवं कल्याण का ध्यान रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। डॉ यादव ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की राशि बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।

खिलौनों पर BIS प्रमाणन अनिवार्य

भारत सरकार स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए खिलौनों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रही है, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण (बीआईएस प्रमाणन), खिलौना क्लस्टर स्थापित करना और आत्मनिर्भर भारत के तहत ष्वोकल फॉर लोकलष् को बढ़ावा देना शामिल है। जिसके तहत 1 जनवरी, 2021 से भारत में निर्मित या आयातित सभी खिलौनों के लिए ISO 8124 मानकों पर आधारित अनिवार्य BIS प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पूरे उद्योग में उच्च सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

कैबिनेट बैठक

मध्य प्रदेश ने देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर रिकॉर्ड बनाया है। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में इसकी जानकारी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत 1763 करोड़ रुपये की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 973 सड़कों का निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 29,540 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है।

कूनो-चीता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की धरती ने चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर, उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का

हिस्सा बनाया है। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में 2 मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में चीता पुनर्स्थापना का यह प्रोजेक्ट सफलता के साथ में आयामों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्तमान में चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कूनो नेशनल पार्क में और 03 गांधी सागर अभ्यारण्य में है।

खरगोन - सहकारिता मंत्री, विश्वास सारंग

सहकारिता मंत्री और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम तेल खाने, ईंधन की बचत करने और एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

खरगोन में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री सारंग ने कहा कि वर्तमान समय में युद्ध जैसे हालातों के चलते पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल और ईंधन पर असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि तेल की खपत कम होगी तो देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे फिजूलखर्ची वाले आयोजनों से बचने की भी अपील की है।

संक्षिप्त समाचार

1- जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आगरमालवा जिले के सोयतकलां में जल संरक्षण का संदेश देने हेतु कल एक विशाल भव्य जल कलश यात्रा निकाली गई।
2- नीमच जिले के जावद में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन अभियान परिषद जावद द्वारा सरवानिया महाराज स्थित बालाजी मंदिर राम घाट पर 'जल स्त्रोत सेवा समागम' कार्यक्रम आयोजित किया गया।
3- शिवपुरी जिले में भी 23 मई तक गेहूं खरीदी होगी, कलेक्टर ने किसानों की स्वीकृति लंबित न रखने के निर्देश दिए हैं।
4- अशोकनगर में आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा आज जिला जेल में दिव्यांजन केम्प का आयोजन किया गया।
5- सीहोर कलेक्टर बालागुरू के. ने आज जनगणना कार्य की समीक्षा की, उन्होंने बैठक में जनगणना कार्य में गति लाने के सख्त निर्देश भी दिए।
6- आगरमालवा जिले की नलखेड़ा तहसील के ग्राम डोकरपूरा में आज प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 35 बीघा बहुमूल्य शासकीय गोचर भूमि को मुक्त कराया गया।
7- मंडला पुलिस द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नैनपुर में बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई।

8- राजगढ़ में आयोजित समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जल गंगा संवर्धन अभियान, ई-ऑफिस, आधार निर्माण, ई-केवाईसी, सार्थक अटेंडेंस एवं समय सीमा के प्रकरणों की स्थिति पर विभागवार चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।